भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1775
उत्तर देने की तारीख 10.12.2025

उत्तर प्रदेश में स्थानीय उद्योग, शिक्षा और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी समर्थन

1775. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थानीय उद्योग, शिक्षा और सतत विकास को समर्थन देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो जिले में स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं, विकसित प्रयगशालाओं और प्राप्त परिणाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी, हाँ।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को सहायता एवं बढ़ावा देने के लिए "औद्योगिक अनुसंधान और विकास (आईआरडी)" नामक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम चला रहा है, जिसमें बर्ड-सीआरएफ, पेस (पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास) और ए2के+ स्कीमें शामिल हैं। विभाग की स्कीमें राज्य विशिष्ट की नहीं हैं। बर्ड-सीआरएफ का उद्देश्य सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों/अनुसंधान संगठनों में सामान्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सीआरटीडीएच) स्थापित करना है ताकि एमएसएमई को उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से नवाचारी उत्पादों और नई तकनीकों के परीक्षण के साथ-साथ अनुसंधान और विकास करने में सहायता प्रदान की जा सके। विभाग ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए, समर्पित औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 18 सीआरटीडीएच केंद्रों को सहायता प्रदान की है। पेस स्कीम नए उत्पादों

और प्रक्रियाओं के व्यवसायीकरण के उद्देश्य से प्रयोगशाला स्तर पर प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन के लिए भारतीय उद्योग और अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को सहायता प्रदान करती है। ए2के+स्कीम, ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रमों, विशिष्ट प्रौद्योगिकी मामलों पर किए गए अनुसंधान के निष्कर्षों और परिणामों के दस्तावेजीकरण संबंधी अध्ययन और महिलाओं द्वारा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता प्रदान करती है, ताकि ए2के+स्कीम की घटक "महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग कार्यक्रम" (टीडीयूपीडब्ल्यू) के तहत अधिक संचालन कुशलता प्राप्त की जा सके। डीएसआईआर की स्कीमें परियोजना मोड में कार्यान्वित की जाती हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचनाएँ विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जो डीएसआईआर का एक स्वायत्तशासी संगठन है, भी कोई राज्य विशिष्ट स्कीम नहीं चला रहा है और समूचे भारत में सीएसआईआर की प्रयोगशालाएँ हैं, जो सतत प्रौद्योगिकी विकास के लिए स्थानीय उद्योगों/एमएसएमई को सहायता प्रदान कर रही हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अमरोहा जिले में निष्पादित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

सीएसआईआर-अरोमा मिशन के तहत, सीएसआईआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स (सीएसआईआर–सीमैप), लखनऊ, प्रायोजित परियोजनाओं के ज़रिए अमरोहा ज़िले में मेंथॉल मिंट जैसी एरोमैटिक फसलों की खेती के साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी-लेड डेवलपमेंट को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2022-2025 की पहल के तहत, अमरोहा और संभल के किसानों के बीच मेंथॉल मिंट की उच्च क़िस्मों और खेती की प्रौद्योगिकी, विशेषकर सीआईएम-उन्नति और अर्ली मिंट टेक्नोलॉजी का विस्तार किया था। इन प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को 1000 एकड़ एरिया में 900 से ज़्यादा किसानों ने प्रदर्शित किया और अपनाया जिससे खेती, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, तेल की पैदावार, गुणवत्ता और खेती से आय में कुल मिलाकर काफी सुधार हुआ। सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (सीएसआईआर-आईआईटीआर), लखनऊ ने "उत्तर प्रदेश के यमुना बेसिन, सेंट्रल गंगा बेसिन और राम गंगा बेसिन के तहत पीज़ोमीटर और मॉनिटरिंग कुओं से इकट्ठा किए गए सैंपल के ज़रिए ग्राउंड वॉटर की गुणवत्ता का आकलन" नामक एक प्रायोजित परियोजना पूरी की है। यह परियोजना ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट (जीडब्ल्यूडी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित की गई है। वर्ष 2021 में इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के राम गंगा बेसिन के तहत 04 ज़िले कवर किए गए थे, जिनमें से एक अमरोहा भी था।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) भी समूचे देश में अपनी बायो-राइड (बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट) स्कीम के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में भी लागू है। वर्तमान में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कोई परियोजना नहीं चला रहा है।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) जिसे पहले एसईआरबी कहा जाता था, एक नेशनल फंडिंग एजेंसी है जो समूचे देश में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है और रिसर्च और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देती है। एएनआरएफ ने साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एआरजी, पीएमईसीआरजी, आईआरजी, पीएआईआर, एमएएचए ईवी मिशन, एनपीडीएफ, रामानुजन फेलोशिप, जे.सी. बोस अनुदान आदि जैसे कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। संगठन के पास कोई जिला विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है और सभी कार्यक्रमों के लिए समूचे देश हेतु खुले आमंत्रण की घोषणा की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

*** * * * * * ***